

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व अपील संख्या :- 11/2015

निर्णय दिनांक :- 16-02-2021

अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1. भगवानलाल, मादुलाल, पुरणमणी पिता-चतरभुज जाति-माली, नि०-आकोला तहसील- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. चुन्नीबाई, मु० घापू बाई, मु० रुक्मणबाई पिता-चतरभुज नि०-आकोला (भूपालसागर) 2. सुखलाल, शिवलाल, रतनलाल, मधुरालाल पिसरान किराना जाति-माली, नि०-आकोला 3. मु० लाली, मु० देह पिसरान जयचन्द्र जाति-माली नि०-आकोला (भूपालसागर)

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956



वकील अपीलांत ने एक राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

- यह है कि ग्राम आकोला में चतरभुज, किराना, लाली एवं देवली पिता श्री जयचन्द्र माली के सह खातेदारी की आराजियात का विभाजन सहायक भू-आमिलेख अधिकारी ने कर दिया। सह खातेदारों में से चतरभुज एवं किराना का देहान्त हो गया है जिससे चतरभुज के वारिसान अपीलांत संख्या- 1, 2 व 3 एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या- 1, 2 व 3 हैं। सह खातेदार किराना के वारिसान रेस्पोंडेन्ट संख्या- 4, 5, 6, 7 हैं।
- यह है कि सह खातेदारी की आराजियात का विभाजन करने का अधिकार पैमाइश विभाग को नहीं है फिर भी सह खातेदारों की सहमति के आधार पर विभाजन अधीनस्थ सहायक आमिलेख द्वारा निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरित है।
- यह है कि सह खातेदार लाली व देह का हिस्सा बिना किसी आधार

— लगातार —

एवं अधिकार के पैमाइश विभाग ने तर्क कर दिया जबकि इस बाबत कोर्ट पंजीकृत हस्तांतरण का दस्तावेज नहीं है। अतः अपील अपीलॉट स्वीकार की जाकर खसरा परिशोधन क्रमांक-21 पर पारित आदेश दिनांक 27-06-1984 को निरस्त फरमा उक्त परिशोधन पत्र में अंकित आराजियात को पुनः सह खातेदारी में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलॉट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। बाद तामिल रेस्पोंडेन्ट्स संख्या-1,2,3,4 व 6 गैर हाजिर रहे, जिससे इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अपीलॉट ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 5,7,8 व 9 के विरुद्ध किसी प्रकार की कोर्ट दाद/सहायता नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु रखी गयी। रेस्पोंडेन्ट्स के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के कारण वकील अपीलॉट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील अपीलॉट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ सहायक भू अभिलेख अधिकारी ने सेजाधिकार से बाहर जाकर गैर कानूनी तरीके से सह खातेदारी की आराजियात का विभाजन कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। पैमाइश विभाग ने बिना किसी पंजीकृत हस्तांतरण के दस्तावेज के सह खातेदार लाली व देहू का हिस्सा तर्क कर दिया जो कि विधि विरुद्ध है अतः खसरा परिशोधन क्रमांक-21 पर पारित आदेश दिनांक 27-06-84 को निरस्त फरमा कर वायस्त आराजियात को पुनः सह खातेदारी में दर्ज किया जावे।



A-1/2/3 वकील अपीलॉट ने अपनी अपील के समर्पण में खसरा परिशोधन सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूप्रशासकी जिला जिला (का) प्रतिलिपी पेश की गयी। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अपीलॉट वकील की बहस सुनी गयी।

खसरा परिशोधन पत्र (विभाजन से संबंधित) संवत् 2071 के पृष्ठ क्रमांक-907 से यह स्पष्ट होता है कि अपीलॉट-1,2,3 के पिता व रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1,2,3 के पिता चतरभुज, रेस्पोंडेन्ट्स सं.-4,5,6,7 के पिता किशाना तथा हीरा व डालू ने जरिये प्रार्थना-पत्र पेश कर आपसी रजामंदी व उस समय पर मौके पर जमीन के कस्जे-काब्रत के मुताबिक बंटवाश कियाथा तथा इन सभी सह खातेदारों के सहमति के हस्ताक्षर भी खसरा परिशोधन पत्र पर अंकित हैं, इसके साथ ही स्वयं अपीलॉट के भी स्वीकार किया है कि 27-06-84 को पारित परिशोधन पत्र अपीलॉट

— लगातार —

व रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वजों द्वारा सहमति से पारित किया गया। तब से लेकर आदिनांक तक पूर्ववत बंटवाह मुताबिक अपीलॉट व रेस्पोंडेन्ट्स का विज काश्त है। इसके साथ ही अपीलॉट द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद भी चलने योग्य नहीं है क्योंकि लगभग 30 वर्षों बाद अपीलॉट द्वारा अपील की गयी, जबकि अपीलॉट के पिता ने सहमति से 23.06.1984 को बंटवाह अमल दुरामद करवाया था। अपीलॉट द्वारा अपील में की गयी देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया है अतः प्रार्थना-पत्र धारा-5 कानून म्याद भी चलने योग्य नहीं है। इसके साथ ही लगभग 30 वर्षों से अपीलॉट व रेस्पोंडेन्ट्स व उनके वारिसान कब्जा-काश्त के अनुसार वर्तमान में भी का विज है। अपीलॉट यदि उक्त खसरा परिशोधन-पत्र में दर्जामे जाये सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के सहमति के बंटवाह को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन, अपीलॉट व हस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलॉट की अपील अंतर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/02/2021

सुखाराम पिण्डे (RAS)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

